एफपीआई की 25,472 करोड़ की निकासी

डेट और हाइब्रिड उपकरणों में सीमित निवेश

डॉलर की मजबूती और बेहतर वैश्विक रिटर्न बने बड़ी वजह

मुंबई, 24 अप्रैल. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की लगातार बिकवाली ने भारतीय पूंजी बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है. मई महीने में अब तक एफपीआई ने भारतीय बाजार से 25,472 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर बेहतर रिटर्न, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती और रुपये में गिरावट की आशंका के कारण विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बना रहे हैं.

ताजा आंकड़ों के अनुसार मई में एफपीआई का इक्विटी निवेश 30,374 करोड़ रुपये घट गया है. हालांकि डेट और हाइब्रिड निवेश साधनों में सीमित खरीदारी देखने को मिली है. विदेशी निवेशकों ने डेट बाजार में 4,563 करोड़ रुपये और हाइब्रिड उपकरणों में 1,036 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है. इसके बावजूद कुल मिलाकर पूंजी बाजार से बड़ी निकासी जारी है. म्यूचुअल फंड में भी एफपीआई निवेश में गिरावट दर्ज की गई है और यहां उनका शुद्ध निवेश 702 करोड़ रुपये कम हुआ है.

यह लगातार तीसरा महीना है जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में बिकवाल बने हुए हैं. इससे पहले अप्रैल में एफपीआई ने 70,786 करोड़ रुपये और मार्च में रिकॉर्ड 1,26,991 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी. फरवरी में कुछ राहत देखने को मिली थी, जब विदेशी निवेशकों ने बाजार में निवेश बढ़ाया था, लेकिन जनवरी में भी वे बिकवाली के पक्ष में थे.

इस कैलेंडर वर्ष में अब तक एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार से कुल 2,14,473 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी कर चुके हैं. इनमें सबसे अधिक दबाव इक्विटी बाजार पर रहा है. केवल इक्विटी से ही अब तक 2,22,343 करोड़ रुपये निकाले जा चुके हैं. यह आंकड़ा वर्ष 2025 के पूरे साल की कुल निकासी 1,66,283 करोड़ रुपये से भी अधिक है.

सोना-चांदी में बड़ी गिरावट, निवेशक सतर्क

नई दिल्ली, 24 मई. कीमती धातुओं के बाजार में शुक्रवार को गिरावट का माहौल देखने को मिला. सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कमजोरी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के बीच सतर्कता बढ़ गई है. राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार से लेकर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) तक दोनों धातुओं में दबाव नजर आया. विशेष रूप से चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोना भी कमजोर होकर बंद हुआ.

एमसीएक्स पर जून डिलीवरी वाला सोना 1018 रुपये टूटकर 1,58,588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 1,58,104 रुपये तक नीचे चला गया था. वहीं जुलाई डिलीवरी वाली चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली और यह 3283 रुपये फिसलकर 2,71,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. दिन के कारोबार में चांदी का भाव 2,69,500 रुपये तक लुढ़क गया था.

एमसीएक्स बाजार बंद रहने के कारण शुक्रवार के बंद भाव ही लागू रहे. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार भी सोने और चांदी की कीमतों में

रिजर्व बैंक ने खरीदा 180 किलोग्राम सोना

एक वर्ष में केंद्रीय बैंक ने करीब 940 किलोग्राम स्वर्ण भंडार बढ़ाया

वैश्विक तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीद से सोने की कीमतों में तेजी

मुंबई, 24 मई . भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने स्वर्ण भंडार को और मजबूत करते हुए तीन अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 180 किलोग्राम सोना खरीदा है. मौजूदा बाजार कीमत के आधार पर इस खरीद का मूल्य लगभग 261 करोड़ रुपये आंका गया है. वैश्विक आर्थिक और भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बैंक लगातार सोने में निवेश बढ़ा रहा है, जिसे सुरक्षित निवेश का सबसे भरोसेमंद माध्यम माना जाता है.

आरबीआई के मई 2026 बुलेटिन के अनुसार 24 अप्रैल तक केंद्रीय बैंक के पास कुल 880.52 टन सोना था. इससे पहले जारी रिपोर्ट में यह भंडार 880.34 टन दर्ज किया गया था. इस प्रकार एक महीने के भीतर 180 किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से तीन अप्रैल को समाप्त सप्ताह में हुई खरीदारी का परिणाम है.

देश में इस समय सोने की कीमत लगभग 1.45 लाख रुपये प्रति दस ग्राम चल रही है. इस हिसाब से एक किलोग्राम सोने की कीमत करीब 1.45 करोड़ रुपये बैठती है.

ऐसे में आरबीआई द्वारा खरीदे गये 180 किलोग्राम सोने का अनुमानित मूल्य लगभग 261 करोड़ रुपये होता है. विशेषज्ञों के अनुसार केंद्रीय बैंक की यह रणनीति विदेशी मुद्रा भंडार को अधिक सुरक्षित और संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के बाद स्वर्ण भंडार दूसरा सबसे बड़ा घटक है. पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है.

> आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष दो मई को केंद्रीय बैंक के पास 879.58 टन सोना था, जबकि अब यह बढ़कर 880.52 टन हो गया है. यानी एक वर्ष के भीतर लगभग 940 किलोग्राम अतिरिक्त सोना खरीदा गया है. वैश्विक स्तर पर जारी व्यापारिक तनाव, युद्ध जैसी भू-राजनैतिक परिस्थितियां और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के कारण दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं. अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाओं ने निवेशकों को सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर आकर्षित किया है. इसका सबसे बड़ा लाभ सोने को मिला है.

आईटीआर फाइलिंग से पहले तैयार रखें जरूरी दस्तावेज

नयी दिल्ली, 24 मई आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और टैक्स विशेषज्ञ समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दे रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि बिना तैयारी के रिटर्न भरने से गलतियां होने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे बाद में आयकर विभाग की ओर से नोटिस या रिफंड में देरी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं.

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनियों और संस्थानों से उम्मीद की जा रही है कि वे 15 जून 2026 तक कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर देंगे. यह दस्तावेज वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें वेतन, टैक्स कटौती और टीडीएस से जुड़ी पूरी जानकारी होती है.

टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार आईटीआर दाखिल करने से पहले सबसे पहले सैलरी और टैक्स रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज एकत्र कर लेने चाहिए. इनमें फॉर्म 16, फॉर्म 16ए और फॉर्म 16बी शामिल हैं. फॉर्म 16ए गैर-वेतन आय पर कटे टीडीएस की जानकारी देता है, जबकि फॉर्म 16बी संपत्ति लेनदेन से जुड़े टीडीएस के लिए उपयोग होता है. इसके अलावा एनुअल

टाटा समूह की दो कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी

टीसीएस देगा प्रति शेयर 31 रुपये डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट 25 मई, योग्य निवेशकों को मिलेगा लाभ

नयी दिल्ली, 24 मई. शेयर बाजार में इस सप्ताह डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है. टाटा समूह की दो प्रमुख कंपनियां — टाटा कंसल्टेंसी सर्विसस को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी. दोनों कंपनियों ने अपने निवेशकों के लिए नकद डिविडेंड की घोषणा की है, जिससे बाजार में इन शेयरों को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने प्रति शेयर 31 रुपये डिविडेंड देने का फैसला किया है. कंपनी ने इसके लिए 25 मई को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है. रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है, जिस दिन तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होते हैं, वे डिविडेंड पाने के पात्र माने जाते हैं.

> टाटा समूह की एफएमसीजी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए प्रति शेयर 10 रुपये डिविडेंड की घोषणा की है. कंपनी की भी रिकॉर्ड डेट 25 मई तय की गई है. इससे पहले पिछले वर्ष कंपनी ने प्रति शेयर 8.25 रुपये का डिविडेंड दिया था. शुक्रवार को कंपनी का शेयर बीएसई में 1192.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. पिछले एक वर्ष में कंपनी के शेयर में लगभग 5.88 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है. यह प्रदर्शन उस समय आया है जब इसी अवधि में सेंसेक्स सूचकांक में करीब 6.84 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली. दीर्घकालिक निवेशकों के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है. पिछले दो वर्षों में कंपनी ने करीब 7.74 प्रतिशत रिटर्न दिया है.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टीसीएस का शेयर 0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2317.25 रुपये पर बंद हुआ. इससे पहले जनवरी 2026 में भी कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी थी, जब उसने अपने योग्य शेयरधारकों को प्रति शेयर 46 रुपये का डिविडेंड दिया था.

हालांकि पिछले कुछ समय से टीसीएस के शेयरों में कमजोरी देखी गई है. पिछले छह महीनों में कंपनी के शेयर करीब 26 प्रतिशत टूट चुके हैं. वहीं एक वर्ष में इसमें लगभग 33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. दो वर्षों में यह गिरावट 39 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि पांच साल तक निवेश बनाए रखने वाले निवेशकों को भी लगभग 24 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है.

मुंबई में घर खरीदना बनता जा रहा सपना

तीन लाख रुपये महीना कमाने वालों के लिए भी 2बीएचके फ्लैट पहुंच से बाहर

नयी दिल्ली, 24 मई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में घर खरीदना अब केवल मध्यम वर्ग ही नहीं, बल्कि ऊंची आय वाले लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. आसमान छूती प्रॉपर्टी कीमतों और धीमी आय वृद्धि के बीच महानगर का हाउसिंग संकट एक बार फिर चर्चा में है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस मुद्दे को नई बहस का केंद्र बना दिया है.

उद्यमी गुनीत सिंह तलवार द्वारा साझा किए गए वीडियो में मुंबई के

रियल एस्टेट बाजार की मौजूदा स्थिति को 'टूटी हुई व्यवस्था' बताया गया. उन्होंने कहा कि शहर में एक सामान्य 2बीएचके फ्लैट की कीमत अब दो करोड़ से तीन करोड़ रुपये के बीच पहुंच चुकी है. यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब ऊंची सैलरी पाने वाले पेशेवर भी अपने घर का सपना पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

> तलवार के अनुसार, जो लोग हर महीने तीन लाख रुपये या उससे अधिक कमाते हैं, वे भारत के शीर्ष एक प्रतिशत आय वर्ग में आते हैं. आमतौर पर माना जाता है कि इतनी आय वाला व्यक्ति आरामदायक जीवन जी सकता है, लेकिन मुंबई के मौजूदा हाउसिंग बाजार में यह आय भी पर्याप्त नहीं दिख रही. उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी आय बचा ले और खाने-पीने, किराये, यात्रा तथा अन्य खर्च पूरी तरह बंद कर दे तब भी उसे एक साधारण 2बीएचके फ्लैट खरीदने में 10 से 12 वर्ष लग सकते हैं.

वैश्विक कारकों पर निर्भर शेयर बाजार

मुंबई, 24 मई घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर वैश्विक कारकों और उद्योग के आंकड़ों पर रहेगी.

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर हर दिन अलग-अलग बयान आ रहे हैं. इससे बाजारों में भी उठा-पटक जारी है. एक दिन शेयर बाजार चढ़ता है, अगले दिन फिसल जाता है और फिर अगले दिन चढ़ जाता है. घरेलू स्तर पर अप्रैल माह के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी सप्ताह के दौरान जारी होने हैं. इससे भी निवेश धारणा प्रभावित हो सकती है. दिग्गज कंपनियों में ओएनजीसी और इंडिगो के 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी होने हैं.

पिछले सप्ताह बीएसई के सेंसेक्स में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को तेजी रही जबकि मंगलवार और गुरुवार गिरावट रही. सेंसेक्स 177.36 अंक (0.24 प्रतिशत) की साप्ताहिक बढ़त में बंद हुआ.

सप्ताह के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 75.80 अंक यानी 0.32 प्रतिशत ऊपर 23,719.30 अंक पर बंद हुआ. मझौली और छोटी कंपनियों में ज्यादा तेजी रही.

एशियाई उत्पादकता संगठन की दिल्ली बैठक संपन्न

नयी दिल्ली, 24 मई राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) की मेजबानी में एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) के संचालन निकाय का 68वां सत्र एपीओ विजन 2030 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, नवाचार, क्षमता विकास और उत्पादकता-आधारित विकास जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ सम्पन्न हुआ.

निकाय की 69वीं बैठक लाओ में की जाएगी. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और

आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की मेजबानी में तीन दिन का यह सम्मेलन 20-22 मई तक भारत मंडपम में आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय उत्पादकता संगठनों (एनपीओ) के प्रमुखों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं, उत्पादकता विशेषज्ञों और एपीओ सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

समाचार विशेष

गिरल आंदोलन के बाद फिर चर्चा में भाटी

क्या बदलेंगे राजस्थान की राजनीति के समीकरण?

जयपुर. बाड़मेर के गिरल में मजदूर आंदोलन के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा खुद पर पेट्रोल डालने की घटना ने राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है. इस घटना के बाद प्रदेशभर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं.

जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर खुलकर बोलने से बचती नजर आई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं अशोक गहलोत और टीकाराम जूली ने भाटी के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मजदूरों की लंबे समय से अनदेखी को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया.

गिरल आंदोलन में लगातार पंद्रह दिनों तक मजदूरों के बीच बैठे रहने और फिर आत्मदाह जैसे कदम की कोशिश ने रविंद्र सिंह भाटी को

प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है. इससे पहले सोशल मीडिया पर छोटू सिंह रावणा और भाटी के बीच चली तीखी बयानबाजी से उनकी छवि को नुकसान पहुंचने की चर्चा थी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गिरल आंदोलन ने भाटी को फिर से मजबूत जननेता के रूप में स्थापित कर दिया है.

तीसरे मोर्चे की राह या कांग्रेस के साथ

> राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा तेज है कि यदि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस का दामन थामते हैं तो वे युवा राजपूतों के लिए एक बड़े विकल्प के रूप में उभर सकते हैं. कांग्रेस के पास प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, धर्मेंद्र सिंह राठौर और भंवर जितेन्द्र सिंह जैसे राजपूत चेहरे मौजूद हैं लेकिन पूरे राजस्थान के युवा राजपूत वर्ग को व्यापक स्तर पर जोड़ने वाला चेहरा अभी तक सामने नहीं आया. ऐसे में भाटी को कांग्रेस भविष्य की बड़ी संभावनाओं के रूप में देख रही है. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रविंद्र सिंह भाटी तीसरे मोर्चे की राह चुनते हैं या कांग्रेस के साथ नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं.

राजस्थान की राजनीति में करीब चालीस से पचास सीटें राजपूत प्रभाव वाली मानी जाती हैं, जिनमें मारवाड़, मेवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र प्रमुख हैं.

बंगाल में भाजपा का एजेंडा

कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत जोर देकर कहा था कि वह लोगों को मांस, मछली खाने से नहीं रोकेगी. भाजपा के नेता तो मछली लेकर प्रचार करते थे. भाजपा नेताओं ने मंगलवार को भगवा गमछा रख कर और टीका चंदन लगा कर मांस, मछली खाते हुए फोटो व वीडियो शेयर की थी.

स्टार प्रचारकों में से एक हिमंत बिस्वा सरमा ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा था कि वे ममता से ज्यादा मांस, मछली खा सकते हैं. लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार बनते ही भाजपा ने अपना एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया. भाजपा सीधे ऐलान करके एजेंडा नहीं लागू कर रही है लेकिन नियमों को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोगों को समस्या होने लगी है.

ध्यान रहे पश्चिम बंगाल देश के उन गिने चुने राज्यों में से है, जहां गौमांस की सीमित बिक्री की इजाजत है. सख्त नियमों के तहत ऐसा होता है. जब से भाजपा की सरकार आई है तब से नियमों को इतना सख्त कर दिया गया है कि गौकशी लगभग बंद हो गई है. अपनी जरुरत के लिए गौवंश बेचने वाले लोगों का काम ठप्प हो गया है. इसका नतीज यह हुआ है कि गौमांस जो पहले दो सौ रुपए किलो बिकता था वह छह सौ रुपए किलो बिक रहा है.

रिश्तों, रसूख और राजनीति की टक्कर

शिमला. हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों के बीच इस बार जिला परिषद की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प और प्रतिष्ठापूर्ण बन गई है. कई बड़े राजनीतिक परिवारों के सदस्यों के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला और भी रोचक हो गया है.

भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के वरिष्ठ नेता अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं. पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा, कुल्लू से पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की बहू तथा मंडी के कांग्रेस नेता सोहन लाल के भतीजे के जिला परिषद चुनाव मैदान में उतरने से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

जिला सिरमौर के पाललियों वार्ड से पूर्व विधायक किरनेश जंग के बेटे अरिकेश जंग और पूर्व भाजपा मंत्री सुखराम चौधरी के भतीजे चरनजीत सिंह भी चुनावी मुकाबले में हैं. वहीं, जिला शिमला में कांग्रेस के तीन मंत्रियों रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है. इन नेताओं ने अपने-अपने समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है और उनके समर्थन में जोरदार प्रचार कर रहे हैं.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के जुब्बल-कोटखाई विस क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित मीनाक्षी गाजटा और भाजपा समर्थित रचना नेगी चुनाव मैदान में हैं. कलबोग वार्ड से कांग्रेस समर्थित रेखा चौहान और भाजपा समर्थित नीना चौहान और सरस्वती नगर वार्ड से कांग्रेस समर्थित नेहा और भाजपा की श्वेता में कांटे की टक्कर मानी जा रही है. इसी तरह पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चम्याणा वार्ड से कांग्रेस समर्थित भूपेंद्र कंवर और भाजपा समर्थित कुशल विक्रम सैन, बल्देयां वार्ड से कांग्रेस समर्थित ओपी ठाकुर और भाजपा के भरत भूषण चुनाव मैदान में हैं. इस विधानसभा क्षेत्र में मंत्री अनिरुद्ध सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है.

पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की बहू निर्दलीय दे रहीं टक्कर

जिला परिषद में कुल्लू जिले की मौहल और जेष्ठा वार्ड भी चर्चा में हैं. इस वार्ड से पूर्व मंत्री ठाकुर सत्य प्रकाश की पत्नी चुनावी मैदान में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें कांग्रेस ने समर्थन नहीं नहीं दिया. कांग्रेस ने यहां से पूर्व पंचायत प्रधान इशरा देवी को समर्थित उम्मीदवार बनाया है. भाजपा ने निशा को नए चेहरे के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है. ऐसे में यहां पूर्व मंत्री ठाकुर सत्य प्रकाश की प्रतिष्ठा दांव पर है.

विशेष — ईपीएस और शनमुगम गुट में पैच-अप कराने उतरे वरिष्ठ नेता

एआईएडीएमके में सुलह की कोशिश तेज

चेन्नई. तमिलनाडु में एआईएडीएमके में चल रही टूट के बीच पार्टी के महासचिव एडप्पडी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने जिला सचिवों की बैठक में पार्टी एकता की अपील की है. इसी बीच पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेता सीवी शनमुगम के नेतृत्व वाले गुट और ईपीएस के बीच मतभेद सुलझाने की कोशिशें भी तेज होती दिख रही हैं. पार्टी नेताओं को आशंका है कि लगातार जारी अंदरूनी कलह से पार्टी और कमजोर हो सकती है.

पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह ईपीएस गुट और सीवी शनमुगम के समर्थक गुट के बीच के तनाव को कम करने की कोशिशों में जुटा है. उनका मानना है कि लंबे समय तक जारी आंतरिक मतभेदों से केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को फायदा होगा. इससे एआईएडीएमके की दीर्घकालिक संभावनाओं को नुकसान होगा. इन प्रयासों में अब तक कितनी प्रगति हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब बागी गुट के नेता शनमुगम ने पार्टी की जनरल काउंसिल की जल्द बैठक बुलाने की अपनी मांग दोहराई है. उन्होंन एआईएडीएमके को हाल के वर्षों में मिली लगातार चुनावी हार समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता बताई है. मंगलवार को एडप्पडी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) द्वारा बुलाई गई जिला सचिवों की अनौपचारिक बैठक में कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम भी देखने को मिले.

पहले यह बैठक उनके आवास पर होनी थी, लेकिन अंतिम समय में इसका स्थान बदलकर एआईएडीएमके मुख्यालय कर दिया गया.

दोनो गुटों का अलग-अलग दावा

> ईपीएस गुट के नेताओं ने दावा किया है कि जिला सचिव बैठक में पार्टी के 82 में से अधिकांश शामिल हुए, वहीं बागी गुट का कहना है कि बड़ी संख्या में पदाधिकारी अनुपस्थित रहे. पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डी. जयकुमार प्रमुख अनुपस्थित नेताओं में शामिल थे. बाद में एआईएडीएमके मुख्यालय की ओर से कहा गया कि कुछ जिला सचिवों ने बैठक में शामिल न हो पाने के कारणों की जानकारी पार्टी को दे दी थी.